सस्ती वित्त की आपूर्ति करना सरकार की प्राथमिकता

मुंबई। भारत की बढ़ती आबादी को भी रहने के लिए एक आवास की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीदने योग्य घरों की संख्या वर्ष 2022 तक 100 मिलियन के जितनी ऊँची हो सकती है। वास्तविक रूप से इन अंतरालों को

समझते हुए खरीदने योग्य घरों की जरूरत और आवास इकाइयों की मांग और आपूर्ति दोनों के बीच की अंतरालों को जोड़ने के इरादे से और सस्ती वित्त की आपूर्ति करना ही सरकार के साथ एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। यह बात रवींद्र सुधालकर ईडी और सीईओ रिलायंस होम फाइनेंस ने कही। सुधालकर ने बताया कि अध्ययनों से पता चलता है कि 27 शहरों में लगभग 19000 परियोजनाएं,लगभग 2.5 मिलियन आवास इकाइयां, आरईआर के दायरे में आ जाएंगी। जिससे परियोजना वित्तपोषण के स्रोतों और परियोजना निधियों के इस्तेमाल पर अधिक जवाबदेही आ जाएगी।